[2021] 8 एस. सी. आर 911

सुराजदेव महतो और अन्य

बनाम्

बिहार राज्य

(आपराधिक अपील सं. 1677/2011)

04 अगस्त, 2021

[एन. वी. रमना, सीजेआई, सूर्या कांत और अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्तिगण]

साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य-के आधार पर दोषसिद्धि की अनुजेयता तथ्यों की अभियोजन का मामला है कि जो अपीलकर्ता सं. 01 पीड़ित को उसके घर से बाहर ले गया, उसके साथ हर समय रहा चौथे दिन अपीलार्थी सं 2 जुड़ा इसके बाद, दोनों ने साजिश रची और पीड़ित की हत्या कर दी-तनुसार अपीलार्थी नं. 1 और 2, को धारा 34 के साथ पढित धारा 302 और 120 बी के तहत सजा दी गयी-अपीलार्थी सं 1 न को धारा 364 के तहत दोषी ठहराया गया। उच्च न्यायालय द्वारा कायम रखा गया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर पूरी तरह से विचार करने पर, अभियुक्त के खिलाफ अंतिम बार देखे गए सिद्धांत के अभियोजन पक्ष के अभिवचन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है-चिकित्सा साक्ष्य पीड़ित की हत्या के चौथे दिन होने की अभियोजन की कहानी की पूरी तरह से पुष्टि करता है-अपीलकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए कि उन्होंने पीड़ित की हत्या की क्योंकि उसका अपीलकर्ता संख्या 1 की बहन के साथ कथित रूप से अवैध संबंध था, अभियोजन द्वारा पर्याप्त रूप से साबित किया गया-अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा दी गई झूठी जानकारी और घटना के बाद उसके फरार होन तथा बलपूर्वक उपाय किए जाने के बाद ही अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का उसका आचरण, दोषपूर्ण परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी साबित करने के लिए प्रासंगिक है-जहां तक अपीलकर्ता संख्या 2 का संबंध है, उसके खिलाफ केवल ठोस सबूत यह है कि उसे भी चौथे दिन पीड़ित और अपीलकर्ता संख्या 1 के

साथ देखा गया था-केवल संदेह को किसी भी संदेह से परे अपने अपराध को साबित करने के लिए त्रुटिहीन सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है-इसके अलावा, अपीलकर्ता संख्या 2 के खिलाफ घटना के बाद टालमटोल या फरार होने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है-इस प्रकार, दूसरे अपीलकर्ता के संबंध में अभियोजन मामले में संबंध गायब होने के कारण, दूसरे अपीलार्थी का अपराध शक के कटहारे से परे साबित नहीं हुआ। इसलिए अपीलकर्ता संदेह के लाभ का हकदार है और उसे आरोपो से वैूम किया जाता है, जबकि अपीलकर्ता सं.1 की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा जाता है । दंड संहिता 1860 की धारा 34 के साथ पढित धारा 302, 120 बी और 364 के अंतगर्त 303 आर/डब्ल्यू 34 और एसएस 120 बी और 364

'अंतिम बार देखे गए सिद्धांत' का सार-समझाया गया।

अभिप्रेरणा-प्रमाण-पुष्टिकारक साक्ष्य का महत्वपूर्ण अंश-समझाया गया।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000:धारा. 7 ए-किशोरता-याचिका-अभिनिर्धारितअपराध करने की तिथि पर किशोरता को प्रथम दृष्टया स्थापित प्रस्तुत के लिए कुछ ठोस साक्ष्य प्रस्तुती की प्रारंभिक जिम्मेदारी अभियुक्त पर है-तथ्यों पर, प्रथम अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष पहली बार किशोरता की याचिका दायर की - प्रथम अपीलार्थी द्वारा आधारित दस्तावेज-विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र और विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रवेश पत्र किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं और इस अत्यधिक विलंबित स्थिति में दो दस्तावेजों की सत्यता को सत्यापित करना संभव नहीं है-प्रथम अपीलार्थी द्वारा उठाई गई किशोरता की याचिका को खारिज कर दिया जाता है।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्तियां व्यापक हैं, विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपील में यह न्यायालय आम तौर पर साक्ष्य का एक नया पुनर्मूल्यांकन करने और गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए अनिच्छुक होगा जबकि कुछ असाधारण परिस्थितियो को छोड़कर तथ्यों की समवर्ती निष्कर्ष है। यद्यपि सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम को निर्धारित करना कठिन है, लेकिन यह बार-बार पुष्टि की गई

है कि जहां उच्च न्यायालय का मूल्यांकन कानून या प्रक्रिया की त्रुटियां से दूषित होता है, या साक्ष्य के गलत अध्ययन पर आधारित होता है, या साक्ष्य के साथ असंगत होता है और इस प्रकार एक विकृत निष्कर्ष की ओर ले जाता है, यह न्यायालय निम्नस्थ न्यायालयों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से परहेज करेगा। [पारा 25] [928-सी-ई]

2.1 तत्काल मामले में अभियोजन पक्ष का मामला 'अंतिम बार देखे गए सिद्धांत' के सार पर आधारित है। अंतिम बार देखे गए सिद्धांत को लागू किया जाता है जहां उस बिंदु के बीच का समय अंतराल जब आरोपी और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था और जब पीड़ित मृत पाया जाता है, तो वह इतना छोटा होता है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का अपराधी होने की संभावना असंभव हो जाती है। अंतिम बार देखे गए तथ्य को अलग से नहीं तौला जाना चाहिए या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य से अलग नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए "अंतिम देखे गए सिद्धांत" को समग्र रुप से लागू किया जाना चाहिए। इसलिए, न्यायालयों को न केवल अंतिम बार देखे गए तथ्य पर विचार करना होगा, बल्कि उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा जो मृतक के मृत्यु के पहले और बाद में अभियुक्त की उपस्थिति में अंतिम रूप देखी गई थीं। [पारा 29,30] [929-एफ-जी; 930-ई-एफ]

2.2 तत्काल मामले में अभियोजन पक्ष निस्संदेह यह स्थापित किया कि मृतक को आखिरी बार अपीलार्थियों के साथ जीवित देखा गया था, और उसने अंतिम बार देखे गए बिंदु तक और उसके बाद की घटनाओं के बारे में सबूत भी प्रस्तुत किए हैं। पीडब्लू-2, पीडब्लू-3 क, पीडब्लू-16 और पीडब्लू-17 के बयानों से पता चलता है कि अंतिम बार देखे जाने से पहले मृतक लगातार अपीलार्थी संख्या 1 के साथ थापीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतीम बार दिनांक 9.04.1987 को मृतक को जीवित देखा, और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपदस्थ किया कि उन्होंने अपीलार्थियों के साथ मृतक को देखा था। पीडब्लू-1, पीडब्लू-5 और पीडब्लू 10 से 14 के बयानों के माध्यम से अभियोजन पक्ष ने अंतिम बार देखे गए बिंदु के बाद हुई घटनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। [पारा 31] [930-एफ-एच] बी

2.3 यह निवेदन कि अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाह या तो शिकायतकर्ता पक्ष से संबंधित या करीबी थे और उनके किसी भी स्वतंत्रता गवाह द्वारा पुष्टि के अभाव में गवाही पर

भरोसा नहीं किया जा सकता है, यह बहुत अधिक सारहीन है। यह कानून की दृष्टि से सामान्य बात है कि अभियोजन पक्ष का काम जांच के दौरान एकत्र किए गए सर्वोत्तम साक्ष्य को सामने रखना है। हालाँकि यह आदर्श है कि अभियोजन पक्ष के मामले की स्वतंत्रत गवाहों के माध्यम से पुष्टि की जाए, लेकिन हर मामले में तीसरे पक्ष की उपस्थिति की उम्मीद करना अनुचित होगा।अभियोजन पक्ष के मामले को केवल शिकायतकर्ता पक्ष से संबंधित सभी गवाहों के नीरस अनुरोध पर खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, स्वतंत्रता गवाहों से पूछताछ न किए जाने के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए, यह भी दिखाया जाना चाहिए कि हालांकि सबसे अच्छा सबूत उपलब्ध था, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा इसे रोक दिया गया था। इसके अलावा, पीडब्लू-3 ने ए और अपीलार्थियों को ग्राम के बाहरी इलाके में देखा, जबकि पीडब्लू-4 ने ए और अपीलार्थियों को अपीलार्थी संख्या 2 के घर के अंदर देखा। इनमें से कोई भी गवाह यह दावा नहीं करता कि उसने मृतक और अपीलार्थी को सार्वजनिक स्थान पर देखा है। इस प्रकार, यह अनुमान लगाना अतार्किक नहीं होगा कि इस घटना का कोई स्वतंत्रत गवाह नहीं था। इसके अलावा, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 दोनों का बयान स्वाभाविक लगता है और उनकी जिरह में उनकी गवाही पर अविश्वास करने के लिए कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। [पारा 32,33] [931-ए-ई]

2.4 अपीलार्थियों ने कहा कि भले ही पीडब्लू-3 के बयान को सही माना गया हो, लेकिन उन्होंने ए को अपीलार्थियों के साथ 09.04.1987 को देखा था, जो शव की खोज से दो दिन पहले था।इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया था कि हस्तक्षेप दोनों घटनाओं के बीच की अवधि इस बात से इंकार नहीं कर सकी कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप की संभावना नही है और इस तरह परिस्थितियों की एक निरंतर श्रृंखला नहीं थी।हालांकि यह प्रस्तुति पहली बार में आकर्षक लगती है, लेकिन जब स्वतंत्रता गवाहों पीडब्लू-6 और पीडब्लू-8 द्वारा दी गई गवाही के आलोक में विचार किया जाता है, तो यह पूरी तरह से गलत है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दोनों अपीलार्थियों ने 09.04.1987 की रात को हत्या को अंजाम दिया। पीडब्लू-8, जिसने 11.04.1987 पर ए के शव की खोज की, ने अपदस्थ किया कि उसने पिछली रात ही शव के बारे में अफवाहें सुनी थीं, हालांकि, यह अंधेरा और वन क्षेत्र होने के कारण, वह केवल अगले दिन ही मौके पर आगे बढ़ सका।यह देखते हुए कि शव कम से कम 10.04.1987 से मौके पर पड़ा था, तत्काल अपराध 10.04.1987 को या उससे पहले

किया गया होगा। तत्काल मामले में चिकित्सीय साक्ष्य आगे अभियोजन की कहानी बताता है । पीडब्लू-6, पिकित्सक ने 12.04.1987 को मृतक के शरीर की जांच की। उनकी राय में, ए की मृत्यु के बाद से 36 से 72 घंटे का समय बीत चुका था। इस प्रकार, चिकित्सा साक्ष्य 09.04.1987 को हत्या होने की अभियोजन पक्ष की कहानी की पूरी तरह से पुष्टि करते हैं। निचली अदालतों ने माना कि मृतक की हत्या वास्तव में 09.04.1987 पर हुई थी।इसके विपरीत दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं है। [पारा 34] [931-ई-एच; 932-ए-बी]

2.5 अपीलकर्ता संख्या 1 उन परिस्थितियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहा है जिनमें वह मृतक की संगति से अलग हो गया था। [पारा 35] [932-डी]

2.6 जहां तक पीडब्लू-10 से पीडब्लू-14 के बयानों की विश्वसनीयता का संबंध है, प्राथमिक निवेदन यह है कि पीडब्लू-12 को छोड़कर, अन्य गवाहों में से कोई भी वर्तमान अपीलार्थियों की पहचान करने में सक्षम नहीं था; और यह कि पीडब्लू-12 की गवाही संदिग्ध लगती है क्योंकि यह अत्यधिक असंभव था कि गवाह एक दीपक की रोशनी के माध्यम से अपीलार्थी संख्या 2 को देखने में सक्षम था।यह मानते हुए कि पीडब्लू-10 पीडब्लू-11, पीडब्लू-13 और पीडब्लू-14 के बयान वर्तमान हाथ में मामले में बहुत अधिक मूल्य नहीं जोड़ते हैं, यह सवाल कि क्या पीडब्लू-12 अपीलार्थी संख्या 2 की पहचान कर सका है या नहीं, विशुद्ध रूप से एक तथ्यात्मक मुद्दा है और नीचे की अदालतों ने इसके संबंध में एक समवर्ती दृष्टिकोण लिया है।पीडब्लू-12 अपीलार्थी नंबर 2 की पहचान करने में सक्षम था क्योंकि उसके चेहरे पर चेचक के निशान थे।पुलिस द्वारा दर्ज प्रारंभिक बयान में भी, पीडब्लू-12 ने कहा था कि जिन दो व्यक्तियों के साथ उसने 09.04.1987 की रात को बातचीत की थी, उनमें से एक के चेहरे पर चेचक के निशान थे। [पारा 36] [932-डी-जी]

2.7 अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर पूरी तरह से विचार करने और अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए आधारों पर हर संभव सीमा तक विचार करने का कोई कारण नहीं है। अपीलार्थियों के खिलाफ अंतिम बार देखे गए सिद्धांत के अभियोजन संस्करण पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है। [पारा 37] [932-जी. एच.]

3.1 यदि किसी मामले में उद्देश्य किसी अभियुक्त (अभियुक्तों) को जिम्मेदार ठहराता है और उसके बाद साबित हो जाता है, तो उक्त अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने की संभावना बढ़

जाती है।यही कारण है कि भारी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में, उद्देश्य का प्रमाण पुष्टिकारक साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, साथ ही, साक्ष्य की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी का निर्माण करेगा। [पारा 38] [933-ए-बी]

3.2 इस मामले में अपीलार्थियों का यह ठहराने का उद्देश्य था कि उन्होंने मृतक की हत्या कर दी क्योंकि उसका कथित रूप से अपीलार्थी नंबर 1 की बहन 'आर' के साथ अवैध संबंध था।जबकि किसी भी गवाह ने मृतक के आर के साथ संबंध होने के बारे में विशेष रूप से गवाही नहीं दी है, कुछ उद्देश्य, जैसा कि आरोप लगाया गया है, पीडब्लू-1, पीडब्लू-3ए और पीडब्लू-16 के बयाने मे, पुष्टि मिली है ।पीडब्लू-3ए की गवाही से पता चलता है कि शुरू में प्रथम अपीलार्थी और मृतक के परिवार के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध थे, लेकिन फरवरी के महीने के बाद उनमें खटास आ गई।पीडब्लू-1, जो एक साथी ग्रामीण है, ने पीडब्लू-3ए की गवाही की पुष्टि की। पीडब्लू-16 ने स्पष्ट रूप से पदच्युत किया कि मृतक के 'आर' के साथ अवैध संबंध के संबंध में पंचायत बुलाई गई थी। [पारा 39] [933-बी-डी]

4.1 अपीलार्थी नं. 1 की बहन के साथ मृतक के संबंध होने का तथ्य निश्चित रूप से संदेह से परे स्थापित नहीं किया गया है, लेकिन पंचायत को बुलाने का तथ्य जिससे कि मुद्दा नियंत्रण से बाहर न हो, यह बताता है कि अपीलार्थी नं. 1 का उद्देश्य मृतक को खत्म करना था।घटनाएँ वर्ष 1987 में हुई थीं, जब ग्रामीण भारतीय समाज अटूट रूप से रूढ़िवादी था, और यहाँ तक कि गैर-वैवाहिक संबंधों की थोड़ी सी भी अफवाह तनाव को भड़का सकती थी। इन जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत ने सही ढंग से दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा कथित उद्देश्य को पर्याप्त रूप से साबित किया गया था।अपीलार्थियों के वकील ने उद्देश्य के बिंदु पर कोई ठोस चुनौती नहीं दी है, और इस तरह, उद्देश्य के बिंदु पर अपीलार्थी संख्या 1 के अभियोग में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। [पारा 40] [933-डी-जी]

4.2 दोनों गवाह पीडब्लू-1 और पीडब्लू-5 व्यक्तिगत रूप से 10.04.1987 पर अपीलकर्ता नंबर 1 से मिले और दोनों ने ए. के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। अपीलार्थीथी सं.1 ने पीडब्लु 1 से झूठ बोला और कहा कि सिनेमा देखने के बाद ए अकेले अमवा के तरफ निकले थे जबकि अपीलार्थी सं. 2 दोफ्ता देखने गये थे। दिलचस्प रूप से, अपीलार्थी संख्या 1

ने पीडब्लू-5 को सूचित किया कि ए दिल्ली के लिए रवाना हो गया था ।यह स्पष्ट है कि पहले अपीलार्थी द्वारा प्रदान की गई झूठी जानकारी तलाशी के प्रयासों को रद्द करके अपने अपराध को छिपाने का एक प्रयास था।इसके बाद अपीलार्थी संख्या 1 फरार हो गया और दंडात्मक उपाय किए जाने के बाद ही अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया। अपीलार्थी सं. 1 द्वारा दी गई झूठी जानकारी और घटना के बाद उसका आचरण दोषपूर्ण परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी साबित करने के लिए प्रासंगिक है। [पारा 41] [933-जी-एच; 934-ए-सी]

4.3 तथापि, अपीलार्थी सं. 2 के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में गुणात्मक अंतर है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि वह पहला अपीलार्थी था जिसने मृतक को लुभाया और उसे उक्त अपीलार्थी के साथ सिनेमा देखने के लिए राजी किया। यह न तो उनका मामला है और न ही अभियोजन पक्ष के गवाहों ने यह बयान दिया है कि अपीलार्थी संख्या 2 मृतक के उसके घर से 05.04.1987 को अपहरण में शामिल था। इसे अपराध के पीछे के उद्देश्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।यह अभिलेख पर साबित हो गया है कि प्रथम अपीलार्थी के पास उस मृतक के खिलाफ क्योंकि वह कथित रूप से उसकी बहन के साथ अवैध संबंध रखता था। ऐसा कोई उद्देश्य कथित या सिद्ध नहीं है जिसने अपीलार्थी संख्या 2 को मृतक की हत्या करने के लिए प्रेरित किया हो। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि प्रथम और द्वितीय अपीलार्थी के बीच 08.04.1987 को या उससे पहले कोई परस्पर सहमति हुई थी, या कि उन्होंने ए की हत्या करने के लिए एक साथ कोई साजिश रची थी। अभिलेख पर यह भी कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी संख्या 1 ने द्वितीय अपीलार्थी को मृतक की हत्या करने के अपने इरादे का खुलासा किया। [पारा 42] [934-सी-एफ]

4.4 यह सच है कि अभियोजन पक्ष ने सबूत पेश दिए है इसमें पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 के बयान शामिल हैं, जिन्होंने 09.04.1987 अंतिम से प्रथम और द्वितीय अपीलार्थियों के साथ मृतक को जीवित देखा था। हालाँकि, जब तक कि अंतिम बार देखे गए सिद्धांत को घटनाओं की एक अटूट श्रृंखला का गठन करने के लिए अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है, तब तक दोषसिद्धि केवल इस आधार पर नहीं हो सकती है कि दूसरा अपीलार्थी भी मृतक के साथ मे अपीलार्थी संख्या 1 के साथ मौजूद था जब उन्हें 09.04.1987 पर एक साथ देखा गया था। [पारा 43] [934-एफ-जी]

4.5 यह उल्लेख करना उचित है कि घटना स्थल पर एक जोड़ी चप्पल, एक रूमाल, एक चाकू, जेरीकन और दो लुंगी जैसी कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली और उन्हें जब्त कर लिया गया। जबकि पीडब्लू-16, अर्थात् मृतक के पिता ने अपीलकर्ता संख्या 1 से संबंधित जब्त की गई लुंगी में से एक की पहचान की है, बरामद की गई वस्तुओं में से किसी भी वस्तु का संबंध अपीलार्थी सं. 2 से नही पाया गया। दूसरे अपीलार्थी के खिलाफ एकमात्र ठोस सबूत यह है कि वह भी मृतक और अपीलार्थी संख्या 1 के साथ 09.04.1987 को था, यानी उन्हें अंत में एक साथ देखा गया था। भले ही यह माना जाता है कि पी. डब्ल्यू.-12 द्वारा 09.04.1987 की रात को अपीलार्थी संख्या 2 की पहचान करने वाला बयान सही है, ऐसे साक्ष्य, मृतक की हत्या में दूसरे अपीलार्थी की संलिप्तता के संबंध में एक मजबूत संदेह पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिर, केवल संदेह को किसी भी संदेह से परे अपने अपराध को साबित करने के लिए त्रुटिहीन सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पारा 44] [934-एच; 935-ए-सी]

4.6 अपीलार्थी सं. 1 के विरुद्ध घटना के बाद परिस्थितिजन्य साक्ष्य दिया गया है, अर्थात्, उसने मृतक के ठिकाने का खुलासा नही किया है और फिर घटनास्थल से गुप्त रूप से गायब हो गया जब तक कि उसने अदालत में आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। ऐसी अपीलार्थी सं. 2 के खिलाफ घटना के बाद बचने या फरार होने का ऐसा आरोप कोई नही लगाया गया है। इस प्रकार, जहां तक दूसरे अपीलार्थी का संबंध है, अभियोजन पक्ष के मामले में कडियाँ गायब हैं। नतीजतन, और कारणों से, अपीलार्थी संख्या 2 का मामला अपीलार्थी संख्या 1 से अलग है और अभियोजन पक्ष दूसरे अपीलार्थी के अपराध को संदेह के दायरे से परे साबित करने में सक्षम नहीं हुआ है।इस प्रकार, दूसरा अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है। [पारा 45] [935-सी-ई]

5.1 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 7-क किशोरता के दावे को निर्धारित करने के लिए अदालत द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करती है।इसका प्रावधान मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी "किसी भी अदालत" और "किसी भी स्तर" पर किशोरता का दावा करने में सक्षम बनाता है।हालांकि, प्रावधान का लाभ उठाने के लिए, अपराध की तारीख पर किशोरता को प्रथम दृष्टया स्थापित प्रस्तुत के लिए कुछ ठोस सबूत पेश करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी आरोपी पर है। [पारा 46] [935-ई-एफ]

5.2 प्रथम अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष पहली बार किशोरता की याचिका दायर की। उन्होंने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी एक प्रवेश पत्र के साथ एक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र रखा है, जिसमें अपीलार्थी संख्या 1 की जन्म तिथि 01.03.1970 होने का दावा किया गया है। यह दावा किया गया है कि घटना के समय प्रथम अपीलार्थी की आयु 17 वर्ष थी।जब प्रथम अपीलार्थी द्वारा आधार माने गए दस्तावेजों का इन तय किए गए सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में विश्लेषण किया जाता है, तो वे किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं।अपीलार्थी संख्या 1 का नाम दस्तावेजों पर नहीं आता है, इसके बजाय ये एक 'एस. पी.' के हैं। इस अत्यधिक विलंबित चरण में अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा आधार माने गए दो दस्तावेजों की सत्यता को सत्यापित करना लगभग असंभव है। इसके अलावा, निचली अदालत के अभिलेख से पता चलता है कि प्रथम अपीलार्थी का नाम 'एस. एम.' है न कि 'एस. पी.'। किसी भी ठोस सामग्री के अभाव में यह दर्शाता है कि विषय - दस्तावेज़ केवल प्रथम अपीलार्थी से संबंधित हैं, कोई तथ्य-खोज जांच करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है। नतीजतन, प्रश्नगत दस्तावेजो पर निर्भरता को स्वीकार नहीं किया जाता है और प्रथम अपीलार्थी द्वारा उठाई गई किशोरता की याचिका को खारिज कर दिया जाता है। [पारा 48] [935-जी-एच; 936-ई-जी]

6. जब अपीलार्थी सं. 1 की दोषसिद्धि और सजा स्थापित की जाती है तो द्वितीय अपीलार्थी को आरोपों से बरी कर दिया जाता है। [पारा 49] [936-जी-एच]

अबुज़र हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2012) 10 एस. सी. सी. 489:[2012] 9 एससीआर 244; पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु बनाम जॉन डेविड (2011) 5 एस. सी. सी. 509:[2011] 7 एससीआर 354; राजस्थान राज्य बनाम काशी राम (2006) 12 एससीसी 254:[2006] 8 पूरक।एससीआर 501; सुखर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1999) 9 एस. सी. सी. 507:[1999] 3 पूरक।एस. सी. आर. 314; बदरूद्दीन रुकोंडिम कर्पुडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1981) पूरक एस. सी. सी. 1; रविंदर सिंह गोरखी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006) 5 एस. सी. सी. 584:[2006] 2 पूरक एस. सी. आर. 615; शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एस. सी. सी. 116: [1985] 1 एससीआर 88; मोहम्मद यूनुस अली तरफदार बनाम डब्ल्यू.

बी. राज्य (2020) 3 एस. सी. सी. 747; आर. दामोदरन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 134;सतपाल बनाम हरियाणा राज्य (2018) 6 एस. सी. सी. 610-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 9 एससीआर 244	को पारा 20	से संदर्भित किया गया है
[2011] 7 एससीआर 354	को पारा 21	से संदर्भित किया गया है
[2006] 8 पूरक एसेसहबार 501	को पारा 21	से संदर्भित किया गया है
[1999] 3 पूरक एससआर 314	को पारा 22	से संदर्भित किया गया है
(1981) सप एस. सी. सी. 1	को पारा 22	संदर्भित किया गया है
[2006] 2 पूरक एससीआर 615	को पारा 23	से संदर्भित किया गया है
[1985] 1 एससीआर 88	को पारा 27	से संदर्भित किया गया है
(2020) 3 एससीसी 747	को पारा 27	से संदर्भित किया गया है
(2018) 6 एससीसी 610	को पारा 29	से संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1677/2021

1988 के आपराधिक अपील सं.273 में पटना उच्च नयायालय के क्षेत्राधिकार पटना के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 20.05.2010 से।

सुश्री प्रेरणा सिंह, टी. महिपाल, अधिवक्ता, अपीलार्थियों के लिए।

अभिनव मुखर्जी, श्रीमती बिहू शर्मा, सुश्री प्रतिष्ठा विज, अधिवक्ता, उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सूर्या कान्त, द्वारा दिया गया।

निर्णय

सूर्य कांत, न्यायाधीश

सूरजदेव महतो (अपीलकर्ता संख्या 1) और प्रकाश महतो (अपीलकर्ता संख्या 2) ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2010 को पारित निर्णय को चुनौती दी है, जिसके द्वारा, उनकी दोषसिद्धि और सजा के आदेश दिनांकित 13.05.1988 को अपर सत्र न्यायाधीश-III, नवादा द्वारा पुष्टि की गई थी।दोनों अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 [संक्षेप में, भा.द.सं.] के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और प्रत्येक अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता संख्या 1 को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे उक्त अपराध के लिए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है कि इस निर्देश के साथ कि दंडादेश साथ-साथ चलेंगे।

तथ्य

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि 05.04.1987 को, अरुण (मृतक) और सुंदर प्रसाद (पी डब्लू -17) अरुण के ग्राम मनावन स्थित घर में ठहरे हुए थे, जब सूरजदेव महतो (अपीलकर्ता संख्या 1) और राज कुमार अरुण के पास पहुंचे और उन्हें नवादा ग्राम में सिनेमा देखने के लिए उनके साथ जाने के लिए कहा।जबकि अरुण शुरू में उनके साथ जाने के लिए अनिच्छुक था, वह अंततः सहमत हो गया जब अपीलकर्ता नं. 1 ने खर्च वहन करने के लिए स्वेच्छा से कहा।अरुण के अनुरोध पर, सुंदर प्रसाद (पीडब्लू 17) भी उनके साथ सिनेमा जाने के लिए सहमत हो गए।शो के बाद, राज कुमार और सुंदर प्रसाद 06.04.1987 को मनावन ग्राम लौट आए, जबकि अरुण और सूरजदेव महतो उनके साथ वापस नहीं आए। जैसा कि अरुण वापस नहीं लौटा, रामजी महतो (अरुण के पिता पीडब्ल्यू) (16) ने राज कुमार से पूछताछ की, जिसने उसे बताया कि अरुण और सूरजदेव महतो अमवा ग्राम में अरुण के पास चले गए थे।

3. कुछ दिन और बीत गए और अरुण तब तक घर नहीं लौटा था, इसलिए अरुण के चिंतित परिवार ने उसे वापस लाने के लिए राज कुमार को भेजा। रामजी महतो ने अपने साथी ग्रामीण कैलाश महतो (पीडब्ल्यू 1) से भी अरुण की तलाश में शामिल होने का अनुरोध किया। उन्हें पता चला कि सूरजदेव महतो और अरुण ने 06.04.1987 को उनकी जगह पर जाकर ठहरे थे। वहां 08.04.1987 तक।आगे यह पता चला कि दोनों तब डोप्टा ग्राम चले गए थे जहां अपीलकर्ता नंबर 1 की बहन की शादी हुई थी।इसके बाद, अपीलकर्ता नं. १ १०. ०४. १९८७ को अपने ग्राम मनावन लौट आया, लेकिन अरुण का पता अभी तक अज्ञात था.जब अपीलकर्ता नं. १ से अरुण के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं दी गई, इसके बजाय, वह भी गायब हो गया और अगले कुछ दिनों तक उसे नहीं देखा गया.रामजी के अनुरोध पर, पी डब्ल्यू ने 10.04.1987 को डोप्टा का दौरा किया, लेकिन वह भी अरुण का पता करने में असमर्थ था।चूंकि अरुण अभी भी लापता था, इसलिए रामजी महतो ने अपने भतीजे ईश्वर महतो (पीडब्ल्यू 3 ए) के माध्यम से पुलिस को जानकारी भेजी, जिसकी परिणति सनहा प्रविष्टि संख्या 227, दिनांक 11.04.1987 को दर्ज करने में हुई।

4. इस बीच, राम वृक्ष पासवान (पीडब्लू 8), चौकीदार, सर्कल नंबर 7, ने काकोलात के पास राम सागर अहार (जलाशय) में एक शव की अफवाह सुनी।11 अप्रैल, 1987 को वह मौके पर पहुंचे और मृत शरीर का पता लगाया।उन्हें शव के पास लोहे की एक खंजर और दो लुंगी भी मिलीं।रामवृक्ष पासवान का बयान बाद में पुलिस द्वारा दर्ज किया गया और उसे एक फर्दबयान के रूप में माना गया।इसके बाद, गोविंदपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी रामचंद्र सिंह (पी डब्लू 18) मौके पर पहुंचे और गवाहों की उपस्थिति में शव का पंचनामा प्रतिवेदन तैयार की।घटना स्थल का निरीक्षण करने पर एक जोड़ी चप्पल, एक रूमाल, एक चाकू और प्लास्टिक से बने जेरीकैन जैसी अतिरिक्त सामग्री भी बरामद की गई और जब्त की गई। गवाहों की उपस्थिति में एक जब्ती सूची तैयार की गई।इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

5. 12.04.1987 को रामजी महतो (पी डब्ल्यू 16) को सूचना मिली कि गोविंदपुर पुलिस स्टेशन द्वारा एक पुरुष व्यक्ति का शव लाया गया था।इसके बाद, रामजी महतो कुछ सहकर्मी ग्रामीणों के साथ पुलिस स्टेशन गए और पहचान की कि मृत शरीर उनका पुत्र अरुण का था।

6. इसके बाद जांच उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आगे बढ़ी और पर्याप्त साक्ष्य के संग्रह पर, सूरजदेव महतो (अपीलकर्ता संख्या 1), प्रकाश महतो (अपीलकर्ता संख्या 2), चंदो महतो, शंकर महतो और राज कुमार महतो के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया गया।यह मामला नवादा के अपर सत्र न्यायाधीश-III की अदालत को दौरा सुर्पुद गया था और आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 364,120 बी और 302 तथा 34 के तहत आरोप तय किए गए थे। अभियुक्तगण अपने-अपने दोष को अस्वीकार कर वाद कर वाद का परीक्षण का दावा किया।

7. अंतिम मुकदमे में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 18 गवाहों से जिरह की गई।अभियोजन पक्ष द्वारा किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य सबूतों पर निर्भर था, जिसमें मृतक के पिता रामजी महतो (पी डब्लू 16) का बयान शामिल था.जो अपने बयान में आरोप लगाया कि सूरजदेव महतो (अपीलकर्ता संख्या 1) ने 05.04.1987 को सिनेमा देखने के बहाने मृतक को बहला-फुसलाकर दूर ले गया था। पी डब्लू 16 ने बयान दिया कि अरुण ने उन्हें बताया कि वो जाने के लिए तैयार नहीं था। सूरजदेव ने उनसे कहा कि वह इसका खर्च उठाएंगे। इसके बाद सूरजदेव के दबाव में अरुण सूरजदेव, राज कुमार और सुंदर के साथ वहाँ चला गया। पीडब्लू डायलिसिस 16 भी अभिसाक्ष्य दिया कि यह उनके अनुरोध पर ही ईश्वरी महतो (पी डब्लू 3ए) ने 11 अप्रैल, 1987 को पुलिस को अरुण के लापता होने के बारे में सूचित किया और 12 अप्रैल, 1987 को वह गोविंदपुर पुलिस स्टेशन गया और अरुण के शव की पहचान की। पी डब्लू 16 ने आगे जब्त लुंगियों में से एक की पहचान की, जो सूरजदेव महतो (अपीलकर्ता संख्या 1) से संबंधित थी। पी डब्लू 16 की प्रतिपरीक्षण परीक्षा ने अभियुक्त व्यक्तियों के लिए जिम्मेदार उद्देश्य को भी उजागर किया। अपीलार्थी नं. १ की बहन के साथ मृतक के अवैध संबंध के संबंध में एक पंचायती (गांव की बैठक) आयोजित किए जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच संबंध तनावपूर्ण थे.

8. इसी तरह, ईश्वरी महतो (पी डब्लू 3ए) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने अरुण को अंतिम बार अपीलकर्ता नं. १, राजकुमार और सुंदर के साथ ०५. ०४. १९८७ को देखा था, और उन्हें अपीलकर्ता नं. १ द्वारा सूचित किया गया था कि वे सिनेमा देखने जा रहे थे। ईश्वरी महतो ने पुनः पक्षों के बीच झगड़े पर प्रकाश डाला और कहा कि पहले सूरजदेव और अरुण के परिवार के बीच मुलाकात और न्योता पेट्टानी चलती थीं, लेकिन माघ महीने के बाद यह बंद हो

गई। सुंदर प्रसाद (पी डब्लू 17) ने पी डब्लू - 16 के बयान की पुष्टि की और कहा कि अपीलकर्ता संख्या 1 ने अरुण और राज कुमार पर सिनेमा देखने के लिए उनके साथ जाने का दबाव बनाया। पी डब्ल्यू-17 ने अपीलकर्ता संख्या 1, अरुण और राज कुमार के साथ वह सिनेमा में जाने के लिए भी साक्ष्य दिया और आगे बताया कि सिनेमा के बाद, अपने ग्राम लौटने के बजाय, अपीलकर्ता संख्या 1 ने समूह को कुम्भरावण ग्राम का दौरा करने के लिए मजबूर किया। पी डब्लू-17 ने कहा कि अपीलकर्ता नं. १ के आग्रह पर, वे लोग प्रकाश महतो के घर में रात बिताई (सूरजदेव और अपीलकर्ता नं. १ के बहनोई और रिश्तेदार) अगले दिन, 06.04.1987 को, जब पी डब्लू-17 ने वापस ग्राम लौटने पर जोर दिया, सूरजदेव महतो (अपीलकर्ता नं. 1) ने उन्हें सूचित किया कि वह और अरुण अमवा ग्राम का दौरा करेंगे।

9. अरुण के पिता दिलकेश्वर महतो (पी डब्लू संयोग 2), अभिसाक्ष्य दिया कि अरुण और अपीलकर्ता नं. 1 ने 06.04.1987 की शाम को अमवा ग्राम में घर का दौरा किया और 08.04.1987 तक वहीं रहे। उन्होंने आगे बयान दिया कि "बुधवार को वह अरुण और सूरजदेव से आगे और रहने के लिए कहा, लेकिन सूरजदेव सहमत नहीं हुए और अरुण को अपने साथ ले गए और कहा कि उन्हें डोप्टा जाना था है।"

10. बिपत महतो (पी डब्लू सी 4) ने अभिसाक्ष्य दिया कि गुरुवार, अर्थात्, ०९.०४.१९८७ को, वह अपने पोते से जानकारी पाया कि अरुण कुंभारवन ग्राम में था और प्रकाश महतो (अपीलकर्ता संख्या २) के घर में रह रहा था। चूंकि पी डब्ल्यू 4 अरुण का चाचा था और उसी ग्राम में रहता था, इसलिए वह और उसकी पत्नी अरुण को अपने घर आमंत्रित करने के लिए उनके पास गए। उन्होंने बताया, "हमलोग अरुण, प्रकाश और सूरजदेव से उस स्थान पर मिले थे।मैंने अरुण को अपने घर आने और वहां भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। प्रकाश ने मुझे बताया कि मैंने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की है, इसलिए वे भोजन करने के बाद लौट उनके पास जाएंगे।" उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता नं. 2 का आश्वासन के बावजूद, अरुण उनके स्थान पर नहीं आया। बाद में, जब पी डब्लू-4 की पत्नी फिर से अरुण को फोन करने के लिए गई, तो उसे अपीलकर्ता नंबर 2 की पत्नी द्वारा सूचित किया गया कि अरुण वापस चला गया है। शिवदानी महतो (पीडब्ल्यू)3), जो पी डब्लू 4 का पुत्र है और मृतक के चचेरे भाई है, ने भी ९.०४.१९८७ को कुम्भरावण ग्राम में अरुण की उपस्थिति के बारे में अभिसाक्ष्य दिया.उसके अनुसार, जब वह अपने ग्राम लौट रहा था, तो उसने अरुण को सूरजदेव, प्रकाश,

राज कुमार और शंकर के साथ ग्राम के बाहरी इलाके में देखा और उनसे पूछा कि वे कहां जा रहे हैं, तो सूरजदेव ने पीडब्ल्यू-3 को सूचित किया कि वे सभी काकोलात ग्राम की ओर जा रहे हैं।

11. हम भरत सिंह (पी डब्लू 10), काशी महतो (पी डब्लू 11), राम प्रसाद (पी डब्लू 12), बालेश्वर प्रसाद (पी डब्लू 13) और मथुरा सॉ (पी डब्लू 14) के बयानों पर विचार कर सकते हैं। पीडब्लू फैक्सीबल 10 और पीडब्लू फैक्सीबल 11 ने अभिसाक्ष्य दिया कि 09.04.1987 की रात को, उन्होंने एक मोटर वाहन (ट्रैक्टर) को काकोलाट की दिशा में जाते हुए आवाज सुना था.हालांकि, पीडब्लू-10 और पीडब्लू-11 ने वाहन में यात्रियों को नहीं देखा था।पी डब्लू-12, पी डब्लू-13 और पी डब्लू-14 सभी पी डब्लू-14 की दुकान के पास 09.04.1987 के देर समय तक मौजूद थे और उन्होंने दो व्यक्तियों को काकोलात से लौटने के बारे में गवाही दी। पीडब्ल्यू-12 इससे भी आगे चला गया और कहा कि वह उन व्यक्तियों की पहचान करने में जो पीडब्ल्यू-14 की दुकान के पास रुके थे की पहचान करने में सक्षम थे।अदालत में आरोपी व्यक्तियों को देखने पर, पी डब्लू-12 अपीलकर्ता नं. २ की पहचान उन व्यक्तियों में से एक के रूप में की जो उस रात दुकान पर आए थे.पी डब्ल्यू ने अपनी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि पुलिस ने उसे एक टेस्ट पहचान परेड [संक्षेप में, 'टी आई पी'] में भाग लेने के लिए नहीं कहा था।यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि साक्ष्यों का यह सेट केवल प्रासंगिक है क्योंकि अरुण का शव काकोलात ग्राम के पास राम सागर अहार में पाया गया था।

12. कैलाश महतो (पी डब्लू-1) और उमेश्वर प्रसाद (पी डब्लू-5) के साक्ष्य की भी अभियोजन पक्ष के मामले में कुछ प्रासंगिकता है। पी डब्लू-1 ने अभिसाक्ष्य दिया कि ०९.०४.१९८७ को पी डब्लू १६ द्वारा अरुण की खोज करने के लिए उससे अनुरोध किया गया था। उसने आगे कहा कि अगले दिन, अर्थात्, १०. ०४. १९८७ को वह बाजार गया और वहाँ उसे अपीलार्थी नं. १ मिला। पी डब्लू-1 का दावा है कि जब उसने अरुण के ठिकाने के बारे में उससे पूछताछ की, तो सूरजदेव महतो (अपीलकर्ता संख्या 1) ने उसे बताया कि सिनेमा देखने के बाद, अरुण अमवा ग्राम गया था, जबकि वह डोप्ता ग्राम गया था। पी डब्ल्यू-5 ने भी अभिसाक्ष्य दिया है कि वह १०.०४.१९८७ को हिसुआ के बरनवाल मेडिकल हॉल में सूरजदेव से मिला जहां अपीलार्थी नं. १ ने उसे बताया कि अरुण दिल्ली गया था।

13. चौकीदार सर्कल नंबर 9 के राम बृक्ष पासवान (पीडब्लू - 8) को 11 अप्रैल, 1987 को अरुण का शव मिला था। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने 10.04.1987 की रात को ही राम सागर अहार में एक मृत शरीर की होने का अफवाह सुनी थी। हालांकि, रात का समय और वन क्षेत्र होने के कारण वह अगले दिन ही वहां जा सका। पी डब्लू 6, जो डॉक्टर है जिसने मृत शरीर का पोस्टमार्टम परीक्षण किया था, मृतक के शरीर पर मौजूद चोटों की जांच करने पर, पी डब्लू-6 ने विचार व्यक्त किया कि चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, और मृत्यु से गुजरने वाला समय 36 से 72 घंटे का था।

14. अभियुक्त व्यक्तियों का मामला, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन उनके बयानों में अभिलिखित है, इंकार का एक मामला था। बचाव पक्ष द्वारा किसी अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

15. विचारण न्यायालय इस तथ्य के प्रति सचेत था कि पारिस्थितिक साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त के दोष को साबित करने के लिए साक्ष्य की श्रृंखला पूरी की जानी चाहिए जिससे कि अभियुक्त की निर्दोषिता की सभी परिकल्पना को अपवर्जित किया जा सके।गवाहों के बयानों की व्यापक जांच करने पर, विचारण अदालत ने पाया कि उन परिस्थितियों को समझाने के लिए चश्मदीदों की कमी थी जिसमें मृतक की मृत्यु हो गई थी और रिकॉर्ड पर साक्ष्य चंदो महतो, शंकर महतो और राज कुमार महतो की संलिप्तता स्थापित करने में विफल रहे। तथापि, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभिलेख पर पारिस्थितिक साक्ष्य से यह पता चलता है कि अपीलार्थी नं. १ ने मृतक को ५. ०४. १९८७ को अपने घर से बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया और उसके साथ रहे और ९. ०४. १९८७ को अपीलार्थी नं. २ भी उसमें शामिल हो गए और उसके बाद वर्तमान अपीलार्थियों ने मृतक के साथ षड्यंत्र किया और उसकी हत्या काकोलत के निकट कर दी। बचाव पक्ष द्वारा उठाई गई दलीलों को नकारते हुए, विचारण न्यायालय ने पी डब्लू-16 के साक्ष्यों को पूर्ण रूप से माना और यह अभिनिर्धारित किया कि पी डब्लू-16 के कथित उद्देश्य के साथ-साथ पी डब्लू-16 के द्वारा आपत्तिजनक सामग्री की पहचान ने अपीलार्थियों के दोष को और अधिक सिद्ध किया। जबकि विचारण न्यायालय ने पाया कि अभियोजन द्वारा पेश किए गए मामले में कुछ विसंगतियां थीं, लेकिन उन्हें मामूली विवरण और मामूली विरोधाभास माना गया था.

16. विचारण न्यायालय ने आगे बताया कि अपीलकर्ता नं. 1 ने ऐसा व्यवहार किया था जिसे सामान्य नहीं माना जा सकता था।मृतक के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने पर अपीलार्थी नं. १ द्वारा पी डब्लू-1 और पी डब्लू-5 को दिए गए झूठे और टालने वाले जवाबों का न्यायिक नोटिस भी लिया गया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न लिंक संतोषजनक रूप से साबित किए गए हैं, इसलिए अपीलार्थी नं. १ द्वारा दिए गए झूठे स्पष्टीकरण को साक्ष्य की श्रृंखला में एक अतिरिक्त लिंक के रूप में माना जा सकता है, जो अभियोजन पक्ष के मामले को और अधिक समर्थन प्रदान करेगा। अदालत ने आगे कहा कि जब पूछताछ की जा रही थी, तब अरुण की खोज में मदद करने के बजाय, अपीलकर्ता नं. 1 फरार हो गया, और उसने 18.04.1987 को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जब उसे पेश होने के लिए मजबूर करने के लिए दंडात्मक उपाय किए गए थे। अंत में, अपीलार्थी द्वारा लिए गए बचाव से असंतुष्ट होकर, निचली अदालत ने यह राय व्यक्त की कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अभियोजन के आरोपों का स्पष्ट खंडन और कुछ नहीं बल्कि एक कानूनी दंड की कठोरता से खुद को छुपाने का प्रयास था। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान मामले में पारिस्थितिक साक्ष्य मजबूत था, और परिणामस्वरूप वर्तमान अपीलार्थियों को दोषी ठहराया।

17. अपनी दोषसिद्धि से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।रिकॉर्ड पर साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए तारीख और चरण वार गवाही देने में सक्षम थे। उच्च न्यायालय ने आगे अपीलकर्ता नं. १ द्वारा पी डब्लू को प्रदान की गई गलत जानकारी पर जोर दिया। इन पहलुओं पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने २०.०५.२०१० दिनांकित आक्षेपित निर्णय द्वारा निचली अदालत के निष्कर्षों की पुष्टि की और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और दंड को बरकरार रखा।

18. व्यथित अपीलार्थी अब इस न्यायालय के समक्ष हैं।

<u>तर्क-वितर्क</u>

19. हमने काफी दूरी तक अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील को सुना है।मुख्य तर्क यह है कि पूरा मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है और कथित घटना के लिए कोई चश्मदीद

गवाह नहीं था।विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा किसी स्वतंत्रता गवाह की परीक्षण नहीं की गई थी और सभी गवाह या तो शिकायतकर्ता पक्ष के रिश्तेदार या करीबी दोस्त थे। वकील ने आगे जोर दिया कि नीचे के न्यायालयों ने पी डब्लू-10 से पी डब्लू-14 के साक्ष्य पर भरोसा करके पूरी तरह से गलती की है।जहां तक अपीलकर्ता नं. २ का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया कि उसके खिलाफ केवल शिवदानी महतो (पीडब्ल्यू-3) और बालेश्वर प्रसाद यादव (पीडब्ल्यू-12) के सबूत थे। वकील ने जोर देकर कहा कि पी डब्लू-3 ने मृतक को मृत शरीर की बरामदगी से दो दिन पहले अपीलकर्ता नं. २ के साथ देखा था, और इसलिए पी डब्लू-३ के साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। पी डब्लू-12 के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त करते हुए, यह अत्यधिक असंभव होने का दावा किया गया कि पी डब्लू-12 एक पूर्ण अंधेरी रात में एक लालटेन की रोशनी के माध्यम से ही अपीलकर्ता नं. २ का चेहरा देखने में सक्षम था। विद्वत वकील ने आगे तर्क दिया कि घटना के स्थान पर बरामद चाकू को फोरेंसिक जांच के लिए न भेजने में जांच एजेंसी की विफलता अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक थी। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि निचले न्यायालय केवल 'अंतिम देखा सिद्धांत' के आधार पर अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटियां में पड़ गए।

20. निष्पक्षता से, हम अपीलकर्ता नं. १ द्वारा ली गई एक अतिरिक्त दलील पर ध्यान दे सकते हैं, जो इस न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया गया है। यह दावा किया गया था कि अपीलकर्ता नं. १ घटना की तारीख पर एक 'किशोर' था। ऐसे दावे के समर्थन में, विद्वत अधिवक्ता ने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए 'स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट' की प्रतियों के साथ-साथ एक 'प्रवेश पत्र' पर भरोसा किया, जिसके अनुसार अपीलकर्ता नं. १ का कथित रूप से १.३.१९७० को जन्म हुआ था। घटना की तारीख के रूप में पाया 09.04.1987 से 11.04.1987 के बीच का था, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता संख्या 1 उस समय 17 वर्ष की आयु का था और इसलिए, एक किशोर था।इस दावे को और पुष्ट करने के लिए, अपीलकर्ताओं के विद्वत वकील ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, २०००, की धारा ७ ए के साथ-साथ इस न्यायालय के निर्णय की ओर जो अबुजार हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

21. दूसरी ओर, बिहार राज्य की ओर से उपस्थित विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर साक्ष्य की बारीकी से जांच करने पर दो न्यायालयों द्वारा अपराध का समवर्ती निष्कर्ष निकाला गया है जो इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करता है। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, तमिलनाडु बनाम जॉन डेविड, मामले पर भरोसा जताते हुए यह आग्रह किया गया कि पारिस्थितिक साक्ष्य के मामलों में दोषसिद्धि अनुज्ञेय है।राज्य के वकील ने भावुक होकर तर्क दिया कि वर्तमान मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला हर तरह से पूर्ण है। उन्होंने इस ओर इशारा किया कि पहला, जैसा कि निचली अदालत द्वारा दर्ज किया गया है, उद्देश्य वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से स्थापित था। दूसरा, नीचे के दोनों न्यायालयों ने समवर्ती रूप से अभिनिर्धारित किया है कि मृतक को अंतिम बार अपीलकर्ताओं के साथ जीवित देखा गया था। उन्होंने राजस्थान राज्य बनाम काशी राम का हवाला देते हुए आग्रह किया कि ऐसी स्थितियों में जब मृतक को अंतिम बार आरोपी के साथ देखा गया था, तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि कथित रूप से कहा गया है। अभियुक्तों ने मृतक की हत्या कर दी। यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं द्वारा उपधारणा को खारिज नहीं किया गया है। तीसरा, अपीलकर्ताओं का दोष उनके आचरण से लगाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने न केवल सिनेमा देखने के बहाने मृतक को लुभाया, बल्कि मृतक के ठिकाने के बारे में झूठी और भ्रामक जानकारी भी दी। चौथा, जांच के दौरान की गई जब्ती/बरामदगी अपीलकर्ताओं की भागीदारी स्थापित करती है, क्योंकि घटना के स्थान पर बरामद दो लुंगियों में से एक की पहचान अपीलकर्ता संख्या 1 से संबंधित होने के रूप में की गई थी। पांचवां, मेडिकल जांच से पता चलता है कि मृतक की मौत अप्राकृतिक तरीके से हुई थी और छठा, बरामद मृत शरीर की पहचान अरुण के रूप में की गई है।

22. विद्वत राज्य अधिवक्ता ने आगे व्यक्त किया कि सभी तात्विक गवाहों, पी डब्लू 1 से पी डब्लू 14 ने एक दूसरे के संस्करणों की पुष्टि की है। शेखर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं बदरुद्दीन रुकोंडिम कारपुडे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामलों के निर्णय से बल प्राप्त कर यह अदालत ने कहा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पुनर्विचार के सिद्धांत लागू होते हैं और एक गवाह द्वारा दूसरे गवाह को दिए गए बयान साक्ष्य में स्वीकार्य हैं। उन्होंने यह भी तर्क आग्रह किया कि वर्तमान मामले में टी. आई. पी. की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगी।

23. इस न्यायालय के समक्ष पहली बार किशोर होने के कारण अपीलार्थी नं. १ की दलील के संबंध में, राज्य के वकील द्वारा जोरदार आग्रह किया गया था कि पहले अपीलार्थी ने पूरी तरह से यह जानते हुए कि अदालत द्वारा आदेश दिए जाने पर, उसके द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों का खंडन करने के लिए कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होगा, इस विलंबित समय तक जानबूझकर प्रतीक्षा की थी। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा दिए गए दस्तावेजों में कुछ जरुरी विसंगतियां हैं, उदाहरण के लिए, दस्तावेजों में उनका नाम नहीं था, लेकिन इसके बजाय एक 'सूर्यदेव प्रसाद' का नाम उल्लेख किया गया था। अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए, वकील ने प्रस्तुत किया कि कथित दस्तावेज को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, [संक्षेप में, 'आईईए'] की धारा 35 के संदर्भ में साबित नहीं किए गए हैं और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमारा ध्यान रविन्दर सिंह गोरखी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय की ओर दिलाया गया था, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अभिवाक करने में एक अस्पष्ट विलंब के कारण, अवयस्क होने का अभिवाक नामंजूर कर दिया गया था।

<u>विश्लेषण</u>

24. हमलोग प्रस्तुत अपील में विचारणीय योग्य दो प्रश्न पाते हैं। (क) क्या वर्तमान मामले में दिया गया पारिस्थितिक साक्ष्य इतना दोषारोपण योग्य है कि यह अपीलार्थियों के अपराध को किसी युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करता है? (ख) क्या अपीलकर्ता संख्या 1 घटना की तारीख को किशोर था?

25. प्रारंभ में इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय में निहित शक्तियां व्यापक हैं, फिर भी यह न्यायालय विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपील में साक्ष्य के नए सिरे से मूल्यांकन करने और कतिपय आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर जब तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष निकलता है तो गवाहों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने के लिए सामान्यतः अनिच्छुक होगा। हालांकि सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम को निर्धारित करना कठिन है, लेकिन बार-बार इसकी पुष्टि की गई है कि जहां उच्च न्यायालय का मूल्यांकन कानून या प्रक्रिया की त्रुटियां द्वारा दूषित किया गया है, या साक्ष्य के गलत पठन पर आधारित है, या साक्ष्य के साथ असंगत है और इस प्रकार एक विकृत

निष्कर्ष पर पहुंचा है, यह न्यायालय नीचे के न्यायालयों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से परहेज करेगा।

26. इस तरह के स्व-नियंत्रण के बावजूद, और न्याय के हित में, हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचारपूर्ण विचार किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य को देखने और चर्चा करने का प्रयास किया है कि क्या दोषसिद्धि का समवर्ती निष्कर्ष किसी विकृति से ग्रस्त है और/या क्या अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि कानूनी रूप से और तथ्यात्मक रूप से टिकाऊ है। क्या अभियुक्त का दोष संदेह से परे साबित हो गया है? यह न्यायालय सरद बर्दीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य में पारित प्रमुख निर्णय का विस्तार से उल्लेख किया गया है एवं पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित करने के लिए आवश्यक मानक पर विचार किया है और आगे अभिनिर्धारित किया हैः

> "153. xxx xxx xxx
>
> (1) वे परिस्थितियां जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह से स्थापित की जानी चाहिए।
>
> xxx xxx xxx
>
> (2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के संगत होने चाहिए, अर्थात् उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यात्मक नहीं किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।
>
> (3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।
>
> (4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव प्रत्येक परिकल्पना को बाहर रखना चाहिए, और
>
> (5) साक्ष्य की ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषिता से संगत निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न छोड़ें और यह दर्शित करे कि सभी मानवीय संभाव्यताओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।"

इन पांच प्रमुख सिद्धांतों को कई अवसरों पर दोहराया गया है, जिसमें हाल ही में मोहम्मद युनुस द्वारा तरफदार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और आर दामोदरन बनाम राज्य का पुलिस इन्सपेक्टर द्वारा प्रतिनिधित्व, में लिए गये फैसले शामिल हैं। इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए, हम अब वर्तमान मामले की जांच करेंगे।

28. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थियों के अपराध पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता हैः (i) अंतिम बार देखा गया सिद्धांत और (ii) उद्देश्य और (iii) प्रदत्त झूठी जानकारी और उसके बाद अपीलकर्ताओं का आचरण।

(i) पिछली बार देखा गया सिद्धांत

29. वर्तमान मामले में अभियोजन का मामला 'अंतिम बार देखा गया सिद्धांत' के सिद्धांत पर बहुत अधिक निर्भर करता है। संक्षेप में, अंतिम देखा गया सिद्धांत उस समय लागू होता है जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार एक साथ देखा गया था, और तब पीड़ित मृत पाया गया है, तो उसके बीच का समय अंतराल इतना छोटा होता है कि अपराधी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध करने की संभावना असंभव हो जाती है। तथापि, सतपाल बनाम हरियाणा राज्य वाले मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह चेतावनी दी है कि जब तक अंतिम बार देखे गए तथ्य की किसी अन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है, तब तक यह तथ्य कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के आस-पास देखा गया था, अपने आप में केवल एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य होगा। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित कियाः

> "..... स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यह अपने आप में एक तरह से कमजोर साक्ष्य हो सकता है जिससे आधार पर मात्र दोष-सिद्धि पाया गया हो। लेकिन जब इसे अन्य परिस्थितियों जैसे कि उस समय के साथ जोड़ा जाता है जब मृतक को अंतिम बार आरोपी के साथ देखा गया था, और शव की बरामदगी समय के बहुत करीब थी, तो आरोपी को उन परिस्थितियों के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत स्पष्टीकरण देना चाहिए जिनके तहत मृत्यु हो सकती थी।यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या गलत स्पष्टीकरण देता है, भगौड़ा हो जाता है, तो उद्देश्य सिद्ध हो जाता है और अन्य बातों के साथ-साथ वसूली के रूप में या अन्यथा परिस्थितियों

> की एक श्रृंखला बनाने के रूप में पुष्टिकारी साक्ष्य उपलब्ध होता है जिससे अभियुक्त के अपराध के लिए एकमात्र निष्कर्ष निकलता है, जो निर्दोषिता की किसी भी संभावित परिकल्पना से असंगत है, तो दोषसिद्धि उसी पर आधारित हो सकती है।यदि परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई संदेह या टूट जाता है, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। इसलिए सिद्धांत को लागू करने के लिए प्रत्येक मामले की अपने तथ्यों के आधार पर जांच की जाएगी।"

30. हम यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि "अंतिम बार देखे गए तथ्य" को अलग-थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए "अंतिम देखे गए सिद्धांत" को लागू किया जाना चाहिए। इसलिए, न्यायालयों को न केवल अंतिम बार देखे गए तथ्य पर विचार करना होगा, बल्कि उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा जो मृतक के मृत्यु के पहले और बाद में अभियुक्त की उपस्थिति में अंतिम रूप से देखी गई थीं।

31. वर्तमान मामले में अभियोजन ने निस्संदेह यह स्थापित किया है कि मृतक को अंतिम बार अपीलार्थियों के साथ जीवित देखा गया था। और पिछली बार देखे गये और उसके बाद की घटनाओं तक के बिन्दु के बारे में साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है। पी डब्लू 2, पी डब्लू 3ए, पी डब्लू 16 और पी डब्लू 17 के अभिसाक्ष्य से यह सुझाव मिलता हैं कि अंतिम बार देखे गए बिंदु से पहले, मृतक लगातार अपीलकर्ता नं. 1 के साथ था। पी डब्लू ३ और पी डब्लू ४ वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतिम बार मृतक को ९. ०४. १९८७ को जीवित देखा था, और उन्होंने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने अपीलार्थियों के साथ मृतक को देखा था। पी डब्लू-1, पी डब्लू-5 और पी डब्लू-10 से 14 के बयानों के माध्यम से अभियोजन पक्ष ने पिछली बार देखे गए बिंदु के बाद की घटनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है।

32. यह तर्क कि अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाह या तो शिकायतकर्ता पक्ष से संबंधित थे या उनके करीब थे और हमारी राय में कि किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा पुष्टि के अभाव में उनकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, निराधार है। कानून में यह सामान्य बात है कि

अभियोजन का काम जांच के दौरान एकत्र किए गए सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य को पेश करना है। यद्यपि यह आदर्श है कि अभियोजन पक्ष के मामले को स्वतंत्रता गवाहों के माध्यम से और पुष्ट किया जाए, लेकिन प्रत्येक मामले में तीसरे पक्ष की उपस्थिति की उम्मीद करना अनुचित होगा।इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष के मामले को केवल सभी गवाहों के शिकायतकर्ता पक्ष से संबंधित होने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, स्वतंत्रता गवाहों की गैर-संक्षिप्त परीक्षण के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए, यह भी दिखाया जाना चाहिए कि हालांकि सबसे अच्छा साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उन्हें रोक रखा था।

33. इसके अलावा, पी डब्लू 3 अरुण और अपीलकर्ताओं को कुंभारवन ग्राम के बाहरी इलाके में देखा, जबकि, पी डब्लू 4 ने अरुण और अपीलकर्ताओं को अपीलकर्ता संख्या 2 के घर के अंदर देखा।इन गवाहों में से किसी ने भी मृतक और अपीलकर्ताओं को सार्वजनिक स्थान पर देखने का दावा नहीं किया है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकालना तर्कहीन नहीं होगा कि इस घटना का कोई स्वतंत्रता गवाह नहीं था। इसके अलावा, पी डब्लू 3 और पी डब्लू 4 दोनों का बयान स्वाभाविक लगता है और उनकी प्रतिपरीक्षण में हमारे लिए उनकी गवाही पर अविश्वास करने के लिए कुछ भी पेश नहीं किया गया है।

34. अपीलार्थियों के वकील ने "अंतिम देखे गए सिद्धांत" पर आगे हमला किया और प्रस्तुत किया कि भले ही पी डब्लू 3 की गवाही को सही माना गया, लेकिन उन्होंने अरुण को 09.04.1987 जो कि मृत शरीर की खोज से दो दिन पहले था की अपीलार्थियों के साथ देखा था। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि दोनों घटनाओं के बीच की अवधि किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की संभावना से इंकार नहीं कर सकती और इस प्रकार परिस्थितियों की कोई निरंतर श्रृंखला नहीं थी। जबकि यह तर्क पहली बार में आकर्षक लगता है, लेकिन, जब स्वतंत्र गवाहों पीडब्लू - 6 और पीडब्लू - 8 द्वारा दी गई गवाही के आलोक में विचार किया जाता है, तो यह पूरी तरह से झूठा साबित होता है। अभियोजन का मामला यह है कि दोनों अपीलकर्ताओं ने 09.04.1987 की रात को हत्या की। पी डब्लू 8, जिसने 11.04.1987 को अरुण के शव की खोज की, ने बयान दिया कि उसने इस बारे में अफवाहें पिछली रात ही मृत शरीर के बारे में सुना था, हालांकि, अंधेरा होने और वन क्षेत्र होने के कारण, वह केवल अगले दिन ही मौके पर जाने में सक्षम हो सका। यह देखते हुए कि शव कम से कम

10.04.1987 से मौके पर पड़ा था, तत्काल अपराध 10.04.1987 को या उससे पहले किया गया होगा।वर्तमान मामले में चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन की कहानी को और मजबूत करता है। पी डब्लू 6, डॉक्टर ने 12.04.1987 को मृतक के शरीर की जांच की। उनकी राय में अरुण की मृत्यु के बाद 36 से 72 घंटे का समय बीत गया। इस प्रकार, चिकित्सा साक्ष्य 09 अप्रैल, 1987 को हुई हत्या की अभियोजन की कहानी की पूरी तरह से पुष्टि करता है। हम यह भी नोट करते हैं कि नीचे के न्यायालयों ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है और यह माना है कि मृतक की हत्या वास्तव में 09.04.1987 को हुई थी। हमें इसके विपरीत मत व्यक्त करने का कोई कारण नहीं दिखता।

35. राज्य के वकील इस न्यायालय के निर्णय, जो काशी राम (सुपरा) में पारित है पर भरोसा करने के लिए यह दावा करने के लिए सही प्रतीत होता हैं कि एक बार जब अंतिम बार देखा गया तथ्य साबित हो जाता है, तो अभियुक्त को उन परिस्थितियों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए जिसमें उसने मृतक का साथ छोड़ दिया था। आईईए की धारा 106 के तहत कानून की इस स्थिति पर सतपाल सिंह (सुप्रा) के मामले में विधिवत विचार किया गया, जिसमें, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो आरोपी के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वर्तमान मामले में भी, अपीलकर्ता नं. १ उन परिस्थितियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में असमर्थ है कि वह क्यों मृतक की कंपनी से अलग हो गया था।

36. पी डब्लू 10 से पी डब्लू 14 तक के अभिकथनों की विश्वसनीयता का प्रश्न है, प्राथमिक तर्क यह है कि पी डब्लू 12 के अलावा, कोई अन्य गवाह वर्तमान अपीलकर्ताओं की पहचान करने में सक्षम नहीं था। यह आगे प्रतिवाद किया गया कि पी डब्लू-12 की गवाही संदिग्ध प्रतीत होती है क्योंकि यह अत्यधिक असंभव था कि गवाह अपीलार्थी नं. २ को एक दीपक की रोशनी के माध्यम में देखने में सक्षम था। यह मानते हुए कि पी डब्लू -10, पी डब्लू -11, पी डब्लू - 13 और पी डब्लू -14 के बयान प्रस्तुत मामले के लिए बहुत अधिक मूल्य नहीं जोड़ते हैं, यह प्रश्न कि पी डब्लू - 12 अपीलकर्ता संख्या 2 की पहचान कर सकता है या नहीं विशुद्ध रूप से एक तथ्यात्मक मुद्दा है और नीचे के न्यायालयों ने इसके संबंध में एक समवर्ती दृष्टिकोण अपनाया है। यह कहना पर्याप्त होगा कि पी डब्ल्यू - 12 अपीलकर्ता नं. 2 की पहचान करने में सक्षम था क्योंकि उसके चेहरे पर चिकन चिकन पॉक्स के निशान थे। यहां तक कि पुलिस द्वारा

दर्ज किए गए प्रारंभिक बयान में, पी डब्लू-12 ने कहा था कि दो व्यक्तियों में से एक जिसके साथ उसने 09.04.1987 की रात को बातचीत की थी, उसके चेहरे पर चिकन पॉक्स के निशान थे।

37. अभियोजन पक्ष के सबूतों पर पूरी तरह से विचार करने और हर संभव सीमा तक अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए आधारों पर ध्यान देने के बाद, हमें अपीलकर्ताओं के खिलाफ अंतिम बार देखे गए सिद्धांत के अभियोजन पक्ष के संस्करण पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

38. यदि किसी मामले में उद्देश्य को किसी अभियुक्त के उद्देश्य से जोडा जाए और उसके बाद साबित किया जाता है तो उक्त अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की संभावना बढ़ जाती है।यही कारण है कि अत्यधिक पारिस्थितिक साक्ष्य के मामलों में, उद्देश्य का सबूत एक महत्वपूर्ण पुष्टिकारक साक्ष्य होगा, साथ ही, साक्ष्य की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी भी बनेगा।

39. इस मामले में अपीलार्थियों का उद्देश्य यह है कि उन्होंने मृतक की हत्या कर दी क्योंकि उसका अपीलार्थी संख्या 1 की बहन रीता के साथ कथित रूप से अवैध संबंध था।जबकि गवाहों में से किसी ने भी रीता के साथ मृतक के संबंध होने के बारे में विशेष रूप से बयान नहीं दिया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है, पीडब्ल्यू -1, 3ए एवं 16 के बयान में कुछ पुष्टि नहीं मिलती है। पी डब्लू-3ए की गवाही से यह पता चला है कि शुरू में प्रथम अपीलकर्ता और मृतक के परिवार के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध थे, लेकिन फरवरी के महीने के बाद वह खट्टा हो गयी।पी डब्ल्यू-1 जो एक सहभागिता है, ने पी डब्लू 3ए के साक्ष्य को स्पष्ट रूप से बल दिया है पी डब्लू 16 ने श्रेणीबद्ध तरीके से साक्ष्य दिया कि मृतक के अवैध संबंध के संबंध में एक पंचायत बुलाई गई थी ।

40. मृतक का अपीलकर्ता नं. १ की बहन के साथ संबंध होने का तथ्य निश्चित रूप से संदेह से परे साबित नहीं हुआ है, लेकिन पंचायत बुलाने का तथ्य जिससे कि मुद्दा नियंत्रण से बाहर न हो जाए, यह सुझाव देता है कि अपीलकर्ता नं. १ का उद्देश्य मृतक का उन्मूलन करना था हम इस तथ्य को भूल नहीं सकते कि ये घटनाएं वर्ष 1987 में हुई थीं, जब ग्रामीण भारतीय समाज अनियंत्रित रूप से रूढ़िवादी था, और यहां तक कि अतिरिक्त वैवाहिक मामलों की मामूली अफवाह भी तनाव को बढ़ा सकती थी। इन जमीनी वास्तविकताओं पर विचार करते

हुए, हमारी राय में, निचली अदालत ने सही रूप से दर्ज किया कि जैसा कि अभिकथित किया गया है, उसका उद्देश्य अभियोजन द्वारा पर्याप्त रूप से साबित कर दिया गया था। हम यह भी नोट करते हैं कि अपीलार्थियों के वकील ने उद्देश्य के बिंदु पर कोई ठोस चुनौती नहीं दी है, और इस प्रकार, हम उद्देश्य के बिंदु पर अपीलार्थी नं. १ के अभ्यारोपण में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

(iii) अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा दी गई झूठी जानकारी और उसके बाद का आचरण।

41. अब हम संक्षेप में अपीलकर्ता नं. 1 से पीडब्ल्यू-1 और पीडब्ल्यू-5 द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी पर विचार कर सकते हैं। इन दोनों गवाहों ने व्यक्तिगत रूप से 10 अप्रैल 1987 को अपीलकर्ता संख्या 1 से मुलाकात की और दोनों ने अरुण के ठिकाने के बारे में पूछताछ की.अपीलार्थी नं. १ ने पी डब्लू १ से झूठ बोला और उसे बताया कि सिनेमा देखने के बाद, अरुण अकेला ही अम्वा के लिए चला गया था, जबकि अपीलार्थी नं. २ को डोप्टा का दौरा करना पडा था.इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि अपीलकर्ता नं. १ ने पी डब्लू-5 को सूचित किया कि अरुण दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। यह हमारे लिए स्पष्ट है कि पहले अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी तलाशी के प्रयासों को बाधित करके अपने अपराध को छिपाने का एक प्रयास था। अपीलकर्ता संख्या 1 इसके बाद फरार हो गया और अदालत के समक्ष तब आत्मसमर्पण किया जब केवल दंडात्मक उपाय किए जाने के बाद किया गया था। इस प्रकार, हम राज्य के वकील के साथ सहमत हैं कि अपीलकर्ता नं. १ द्वारा दी गई गलत जानकारी और उसके बाद की घटना का आचरण आपत्तिजनक परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त लिंक साबित करने के लिए प्रासंगिक है।

42. हालांकि, प्रकाश महतो (अपीलकर्ता संख्या 2) के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के नेतृत्व के साक्ष्य में गुणात्मक अंतर है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि यह पहला अपीलकर्ता (सूरजदेव महतो) था जिसने मृतक को आकर्षित किया और उसे सिनेमा देखने के लिए कथित अपीलकर्ता के साथ जाने के लिए राजी किया। यह न तो उनका मामला है और न ही अभियोजन पक्ष के गवाहों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलकर्ता नं. २ ने ५. ०४. १९८७ को मृतक के घर से उसके प्रेरक अपहरण में शामिल था। इसे अपराध के पीछे के उद्देश्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह अभिलेख पर साबित हो गया है कि प्रथम

अपीलार्थी के पास उस मृतक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए साधन था क्योंकि वह कथित रूप से उसकी बहन के साथ अवैध संबंध रखता था।ऐसा कोई उद्देश्य अभिकथित या साबित नहीं है जिससे अपीलार्थी नं. २ को मृतक की हत्या करने के लिए प्रेरित किया हो। इससे भी आगे, अभियोजन पक्ष ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि प्रथम और द्वितीय अपीलकर्ता के बीच 08 अप्रैल, 1987 को या उससे पहले कोई बैठक हुई थी, या कि उन्होंने अरुण की हत्या करने के लिए एक साथ कोई साजिश रची थी। अभिलेख पर भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ता नं. १ ने मृतक अरुण की हत्या करने के अपने इरादे का अपीलकर्ता संख्या 2 को खुलासा किया हो।

43. यह सच है कि अभियोजन पक्ष ने पी डब्लू 3 और पी डब्लू 4 के बयानों को शामिल करते हुए साक्ष्य को नेतृत्व दिया है, जिन्होंने अंतिम रूप से पहले और दूसरे अपीलकर्ताओं के साथ 09 अप्रैल, 1987 को मृतक को जीवित देखा था। हालांकि, जब तक कि घटनाओं की एक अटूट श्रृंखला का गठन करने के लिए अंतिम देखे गए सिद्धांत को अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है, तब तक दोषसिद्धि केवल इस आधार पर नहीं हो सकती है कि अपीलकर्ता-2 के साथ में अपीलकर्ता नंबर 1 भी मृतक के साथ मौजूद था जब उन्हें 9 अप्रैल, 1987 को एक साथ देखा गया था।

44. यह उल्लेख करना उचित है कि कुछ आपत्तिजनक सामग्री जिसमें एक जोड़ी चप्पल, एक रूमाल, एक चाकू, जेरीकैन और दो लुंगी शामिल थे, घटनास्थल से बरामद की गई और जब्त की गई।जबकि पी डब्लू-१६, अर्थात्, मृतक के पिता ने अपीलार्थी नं. १ से संबंधित जब्त लुंगी में से एक की पहचान की है, बरामद की गई किसी भी वस्तु का श्रेय २ और अपीलार्थी-2 को नहीं दिया गया है। दूसरे अपीलार्थी के खिलाफ एकमात्र पर्याप्त साक्ष्य यह है कि वह भी ९. ०४. १९८७ को मृतक और अपीलार्थी नं. १ के साथ था, अर्थात्, उन्हें एक साथ अंतिम बार देखा गया था। भले ही हम यह मान लें कि 09 अप्रैल, 1987 की रात को अपीलकर्ता संख्या 2 की पहचान करने वाले पी डब्लू-12 का बयान सही है, ऐसा साक्ष्य मृतक की हत्या में दूसरा अपीलकर्ता की भागीदारी के संबंध में एक मजबूत संदेह पैदा कर सकता है, लेकिन फिर, केवल संदेह को किसी भी संदेह से परे उसके अपराध को साबित करने के लिए त्रुटिहीन साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, अपीलार्थी नं. १ के खिलाफ घटना के बाद परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, अर्थात्, कि उसने मृतक के ठिकाने का खुलासा नहीं किया और फिर

जब तक उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया तब तक वह चोरी-छिपे घटनास्थल से गायब हो गया। अपीलकर्ता संख्या 2 के खिलाफ घटना के बाद बचने या फरार होने का ऐसा कोई आरोप नहीं है। इस प्रकार, जहां तक दूसरे अपीलकर्ता का संबंध है, अभियोजन पक्ष के मामले में लिंक गायब हैं। नतीजतन, और ऊपर बताए गए कारणों से, हम पाते हैं कि प्रकाश महतो (अपीलकर्ता नं. २) का मामला सूरजदेव महतो (अपीलकर्ता नं. १) के मामले से अलग है और अभियोजन पक्ष संदेह के दायरे से परे दूसरे अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने में सक्षम नहीं रहा है। इस प्रकार, दूसरा अपीलकर्ता संदेह के लाभ का हकदार है।

<u>बी. अपीलकर्ता नंबर 1 की किशोरावस्था की दलील</u>

46. इस बात का कोई खंडन नहीं है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (संक्षेप में, किशोर न्याय अधिनियम) की धारा 7 किशोर के दावे का अवधारण करने के लिए न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करती है। इसका प्रावधान मामले के अंतिम निपटान के बाद भी किसी भी अदालत के समक्ष और किसी भी स्तर पर नाबालिग होने का दावा करने में सक्षम बनाता है। तथापि, उपर्युक्त उपबंध का लाभ उठाने के लिए, अपराध के किए जाने की तारीख को प्रथमदृष्टया किशोर होने का सबूत प्रस्तुत के लिए कुछ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने का आरंभिक जिम्मेदारी अभियुक्त पर है।

47. वर्तमान मामले में, प्रथम अपीलकर्ता ने पहली बार इस न्यायालय के समक्ष किशोरावस्था का अभिवाक उठाया है। उन्होंने हमारे समक्ष बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए एक प्रवेश पत्र के साथ एक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें अपीलकर्ता संख्या 1 की जन्म तिथि 01.03.1970 होने का दावा किया गया है। यह दावा किया गया है कि प्रथम अपीलकर्ता घटना के समय 17 वर्ष का था। अपीलार्थियों के विद्वत वकील ने अबुजार हुसैन (पूर्वोक्त) के निर्णय की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें, इस न्यायालय ने जे जे अधिनियम के प्रावधानों और व्याप्ति के बारे में विस्तार से चर्चा की और निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया:

> "39.3इस बारे में कि कौन सी सामग्री प्रथमदृष्टया न्यायालय को संतुष्ट करेगी और/या प्रारंभिक भार के निर्वहन के लिए वह पर्याप्त है, न तो सूचीबद्ध किया जा सकता है और न ही यह निर्धारित किया जा सकता है

> कि साक्ष्य के किसी विशिष्ट टुकड़े को क्या महत्व दिया जाना चाहिए जो किशोरावस्था की उपधारणा को बढ़ाने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन नियम 12 (3) (क) (i) से (iii) में निर्दिष्ट दस्तावेज निश्चित रूप से नियम 12 के तहत आगे की जांच के लिए आवश्यक उम्र के बारे में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए पर्याप्त होंगे। संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया बयान बहुत अस्थायी है और दावे को उचित ठहराने या अस्वीकार करने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं हो सकता है। किशोरावस्था कीदोषसिद्धि के पश्चात् प्राप्त स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र या मतदाता सूची आदि जैसे दस्तावेजों की विश्वसनीयता और/या स्वीकार्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और कोई कठोर और त्वरित नियम विहित नहीं किया जा सकता कि उन्हें प्रथम दृष्टया स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

48. जब प्रथम अपीलकर्ता द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उनका विश्लेषण इन स्थापित सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में किया जाता है, तो हम पाते हैं कि वे किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। अपीलकर्ता संख्या 1 का नाम दस्तावेजों में नहीं है, इसके बजाय ये एक 'सूर्यदेव प्रसाद' के हैं। इस अत्यधिक विलंबित चरण में अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा भरोसा किए गए दो दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि करना लगभग असंभव है.इसके अलावा, विचारण अदालत के रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रथम अपीलकर्ता का नाम 'सूर्यदेव प्रसाद' नहीं बल्कि 'सूरजदेव महतो' है। किसी भी तर्कसंगत सामग्री के अभाव में, जो इंगित करता है कि विषय-दस्तावेज केवल पहली अपीलकर्ता से संबंधित हैं, कोई भी तथ्य जांच करने का मामला नहीं बनाया गया है.नतीजतन, हम प्रश्नगत दस्तावेजों पर भरोसा करने से इनकार करते हैं और प्रथम अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए किशोर होने के तर्क को खारिज करते हैं।

<u>निष्कर्ष</u>

49. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकृत किया जाता हैजबकि सूरजदेव महतो (अपीलकर्ता संख्या १) की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा

जाता है और उसकी अपील खारिज कर दी जाती है, द्वितीय और अपीलकर्ता (प्रकाश महतो) को आरोपों से बरी कर दिया जाता है। प्रथम अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत बंधपत्र रद्द कर दिए जाते हैं और उसे निर्देश दिया जाता है कि वह आत्मसमर्पण करेगा और उसे शेष सजा भुगतनी होगी। द्वितीय अपीलार्थी के जमानत बंधपत्रों का उन्मोचन किया जाता है।

(एन. वी. रमन), मुख्य न्यायाधीश

(सूर्यकांत), न्यायमूर्ति

(अनिरुद्ध बोस), न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

दिनांकः 04.08.2021

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।